

प्रेस विज्ञप्ति
12.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आँचलिक कार्यालय ने विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित 41.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जो "एचपीजेड टोकन और अन्य" के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने में शामिल पाए गए।

ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें भोले-भाले निवेशकों को "बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी माइनिंग" के लिए पैसा लगाने पर भारी रिटर्न का वादा करके ठगा गया, जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम से एक ऐप आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि इसी तरह से हजारों निवेशकों को ठगा गया है। जालसाजों की कार्यप्रणाली सबसे पहले पीड़ितों को एचपीजेड टोकन ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से उनके निवेश को दोगुना करने के बहाने कंपनी में निवेश करने के लिए लुभाना था। निवेश प्राप्त करने के लिए, विभिन्न फर्जी संस्थाओं के नाम पर विभिन्न बैंक खाते और मर्चेन्ट आईडी खोले गए थे, जिनमें डमी निदेशक/मालिक थे, केवल क्रिप्टो माइनिंग और अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों में निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रतिनिधित्व करने वाले अपराध की आय के रोटेशन/लेयरिंग के उद्देश्य से। 57,000 रुपये के निवेश के लिए 3 महीने के लिए प्रति दिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था। निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए शुरुआत में रिटर्न दिया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक ऑफर प्रस्तावित किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशक और अधिक निवेश कर सकें। इसके बाद, एकत्र की गई धनराशि को निकाल लिया गया। घोटाला जून 2021 में शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2021 तक "एचपीजेड ऐप" और संबंधित वेबसाइटें पहुंच से बाहर हो गईं।

अपराध की आय को कुर्क करने की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी दीमापुर सब-जोनल कार्यालय ने पूरे देश में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों/वर्चुअल खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा बनाए गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के बैलेंस को फ्रीज किया था और 278.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अब तक, इस मामले में ईडी द्वारा फ्रीज और जब्त अपराध की कुल आय 497.20 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।